आज़ादी का अमृत महोत्सव

साप्ताहिक सूचना पत्र

(दिनांक 25.07.2022 से 31.07.2022)

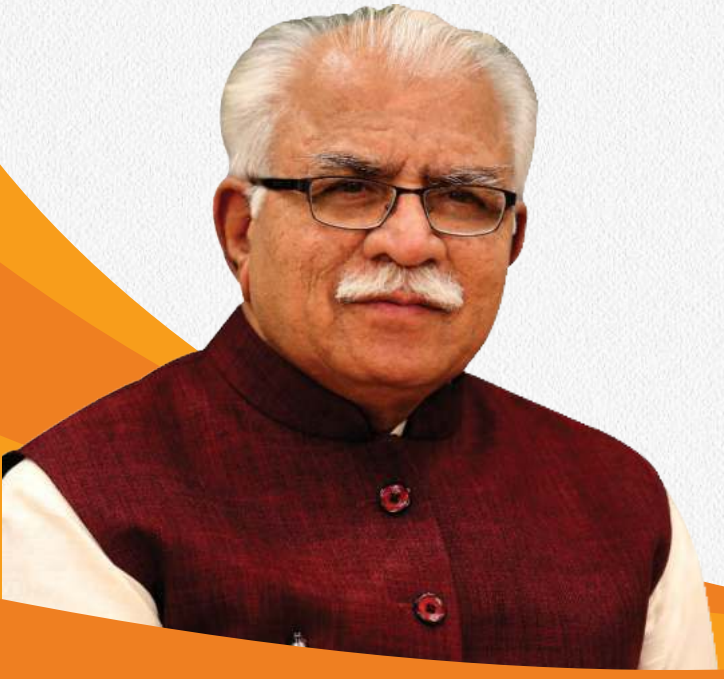

भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा

साप्ताहिक सूचना पत्र

जल संसाधन को लेकर इजराइल के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात

(दिनांक 26.07.22)

विषय: जल संसाधन को लेकर इजराइल के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात।

प्रभाव: माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित अपने निवास स्थान (संत कबीर कुटीर) पर जल संसाधन को लेकर इजराइल के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जल संसाधन के क्षेत्र में हरियाणा और इजराइल मिलकर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में घटते जलस्तर और इजराइल में कम पानी की समस्या है, ऐसे में दोनों मिलकर तकनीक व अन्य विषयों पर काम कर सकते हैं। इससे हरियाणा व इजराइल में पानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा में जल स्तर तेजी से गिर रहा है, ऐसे में प्रदेश सरकार पानी बचाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन) प्राधिकरण बनाया है, जिसके तहत प्रदेश के 18 हजार

साप्ताहिक सूचना पत्र

तालाबों के जीर्णोदार का जिम्मा उठाया गया है। इन तालाबों की सफाई के साथ–साथ इन्हे डिशिल्ट भी किया जा रहा है, ताकि भूमि में पानी की ज्यादा से ज्यादा रिचार्जिंग हो। इसके साथ–साथ प्रदेशभर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लॉट (एसटीपी) लगाए जा रहे हैं। इन एसटीपी के पानी को खेती, निर्माण और घरों में गार्डनिंग के लिए उपयोग करने पर जोर दिया जा रहा है। खेती में ड्रिप इरीगेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। पानी बचाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इजराइल और हरियाणा दोनों ही पानी की चुनौती को समझते हैं। हरियाणा में इंडो इजराइल सहयोग के चार उत्कृष्टता केंद्र चल रहे हैं और पांचवा केंद्र भिवानी में बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को एक टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों को एक दूसरे की तकनीक, अविष्कार और चुनौतियों से सीखने की जरुरत है। इसके लिए टास्क फोर्स काम करे। मुख्यमंत्री जी ने इजराइल के प्रतिनिधिमंडल का आह्वान किया कि वे ऐसे प्रोजेक्ट व प्लॉन हरियाणा में लेकर आएं जिससे पानी का सही इस्तेमाल किया जा सके और कम पानी में भी भूमि की ऊपजाऊ शक्ति को कायम रखा जा सके।

साप्ताहिक सूचना पत्र

शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर रतिया में राज्य स्तरीय कार्यक्रम

(दिनांक 28.07.22)

विषय: शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर रतिया में राज्य स्तरीय कार्यक्रम।

प्रभाव: माँ भारती के वीर सपूत महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह जी के बलिदान दिवस पर 30 जुलाई को रतिया में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शहीद उधम सिंह देश के वीर सपूत थे, जिन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लंदन में जाकर लिया था। 4 जून 1940 को उधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। श्री मनोहर लाल ने कहा कि सरदार उधम सिंह जी का सर्वोच्च बलिदान और उनका मातृभूमि के प्रति समर्पण व त्याग यह देश सदैव याद

साप्ताहिक सूचना पत्र

रखेगा। सभी को देश की अस्मिता और गौरव को बनाए रखने के लिए ऐसे महान क्रांतिकारियों की शहादत और त्याग से प्रेरणा लेनी चाहिए और राष्ट्र निर्माण के लिए आगे आना चाहिए। शहीदों द्वारा दिखाए गए त्याग, बलिदान और देशभक्ति के मार्ग पर चलकर ही हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने महापुरुषों की जयंतियां राज्य स्तर पर मनाने की पहल की है। मुख्यमंत्री जी का मानना है कि हमारे संत–महात्मा, गुरु और महापुरुष न केवल हमारी अमूल्य धरोहर हैं बल्कि हमारी प्रेरणा भी हैं। ऐसी महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की धरोहर हैं। उनकी विरासत को सम्भालने व सहेजने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसलिए 'संत–महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना' के तहत संतों व महापुरुषों के संदेश को जन–जन तक पहुंचाने का काम हरियाणा सरकार कर रही है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक

(दिनांक 28.07.22)

विषय: हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक।

प्रभाव: आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण खेती और किसानों को आगे बढ़ाने के लिए जल्द से जल्द विजन डॉक्यूमेंट–2047 तैयार करे । इसके साथ–साथ प्राधिकरण, किसान कल्याण के लिए खेती से जुड़ी अलग–अलग कमेटियों का भी गठन करे, ताकि इनके सुझावों को भविष्य में सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा सके।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसान प्राधिकरण एक सुपर थिंक टैंक का काम करेगा। इसके तहत खारा पानी, जल भराव, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गीपालन, मशरूम फॉर्मिंग, आर्गेनिक खेती, माइक्रो इरिगेशन आदि विषयों पर कमेटियों का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने प्राधिकरण को निर्देश दिए कि इन अलग–अलग कमेटियों में संबंधित क्षेत्रों के शोधकर्ताओं, विशेषज्ञों, राष्ट्रीय अवार्डी किसानों आदि को शामिल किया जाए। ये कमेटियां संबंधित क्षेत्रों पर गहनता से कार्य करें और सरकार को सुझाव दें ताकि किसानों की आमदनी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके और बेहतर फसल ली जा सके।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसान प्राधिकरण

साप्ताहिक सूचना पत्र

खेती के साथ–साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उनके स्किल डेवलेपमेंट से जुड़े सुझाव भी दे। ताकि किसानों को प्रशिक्षण देकर उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। किसानों के हित के लिए ही इस प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसमें सरकार के सदस्यों

के साथ–साथ खेती, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य आदि के विशेषज्ञों को सदस्यों के तौर पर शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने जोर दिया कि कमेटियों का गठन जल्द से जल्द किया जाए और प्राधिकरण की अगली बैठक भी अतिशीघ्र हो।

राज्य में बारिश के कारण कुछ स्थानों पर जलभराव होने की समस्या पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्षा के कारण होने वाले अतिरिक्त जलभराव की निकासी के प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रबंध किए गए हैं, किसी भी किसान की वर्तमान में बोई गई फसल को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और अगली फसल की समय पर बिजाई करने में भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी।

साप्ताहिक सूचना पत्र

वित्त विभाग द्वारा तैयार पुस्तिका–वित्त विभाग बुलेटिन का विमोचन

(दिनांक 29.07.22)

विषय: वित्त विभाग द्वारा तैयार पुस्तिका–वित्त विभाग बुलेटिन का विमोचन।

प्रभाव: माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज वित्त विभाग द्वारा तैयार एक पुस्तिका – वित्त विभाग बुलेटिन जारी किया है। इस पुस्तिका का उद्देष्य हरियाणा सरकार के सभी विभागों के दिन–प्रतिदिन के कामकाज को सुविधाजनक बनाना है और उन्हें सतत विकास लक्ष्यों के विभिन्न संकेतकों में उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए मानदंड प्रदान करना है।

इस बुलेटिन में समय–समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देश और अधिसूचनाएं शामिल हैं। इसके अलावा, राज्य के बजट आवंटन के साथ–साथ सतत विकास लक्ष्यों के विभिन्न संकेतकों में जिलों और विभागों के प्रदर्शन से संबंधित डाटा को भी शामिल किया गया है। बुलेटिन का शुभारंभ हरियाणा सिविल सचिवालय में किया गया। मुख्यमंत्री जी ने इस पुस्तक के संकलन पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि वित्त विभाग इसे समय–समय पर अपडेट करते रहे।

साप्ताहिक सूचना पत्र

हरियाणा एसडीजी जिला सूचकांक–2022 जारी

(दिनांक 29.07.22)

विषय: हरियाणा एसडीजी जिला सूचकांक–2022 जारी।

प्रभाव: हरियाणा सरकार सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में जिलों के मध्य प्रगति के मूल्यांकन के लिए मुख्यमंत्री जी ने आज यहां भारत के रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव, यूएनडीपी सुश्री शोको नोडा और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हरियाणा एसडीजी जिला सूचकांक – 2022 जारी किया है।

मुख्यमंत्री जी ने वित्त विभाग और स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान को विकास की दिशा मे एसडीजीसीसी जिला सूचकांक 2022 तैयार करने के प्रयासों के लिए बधाई दी।

मुख्यमंत्री जी द्वारा 5 अक्टूबर 2021 को एक प्रोविज़नल जिला सूचकांक फ्रेमवर्क जारी किया गया था। यह संबंधित विभागों के साथ उचित परामर्श के बाद तैयार किया गया दूसरा और अपडेट संस्करण है और यह 115 संकेतकों, 62 लक्ष्यों और 15 गोल्स पर आधारित है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

हरियाणा में अग्निवीर की तैयारियों के लिए दी जाएगी कोचिंग

(दिनांक 29.07.22)

विषय: हरियाणा में अग्निवीर की तैयारियों के लिए दी जाएगी कोचिंग

प्रभाव: मुख्यमंत्री जी ने वायुसेना ट्रेनिंग कमांड, मुख्यालय बेंगलुरू के एयर ऑफिसर– कमांडिंग– इन चीफ एयर मार्शल मानवेन्द्र सिंह के साथ अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के संबंध में बैठक की। केन्द्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत थल सेना, नौसेना व वायुसेना में अग्निवीर के रूप में सेवाएं देने वाले युवाओं को हरियाणा सरकार इसकी तैयारियों के लिए कोचिंग का प्रबंध करेगी। विद्यार्थियों से 11वीं के दाखिले के समय विकल्प लिया जाएगा। आरंभ में प्रदेश के 200 स्कूलों में 50–50 के बैच में इसकी शुरूआत की जाएगी।

बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि शारीरिक व शैक्षणिक अलग–अलग स्तर पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होंगे। शारीरिक प्रशिक्षण के लिए जिला सैनिक बोर्ड तथा इच्छुक भूतपूर्व सैनिक, जो अपनी सेवाकाल के दौरान सेना की ट्रेनिंग संस्थान व भर्ती कार्यालयों में रहे हैं, को वरीयता दी जाएगी। शैक्षणिक पाठ्यक्रम के लिए स्कूल के अध्यापकों की सेवाएं ली जाएंगी। आरंभ में प्रशिक्षण कार्यक्रम सप्ताह के अंत में और बाद में गर्मी की छुट्टियों के दौरान एक

साप्ताहिक सूचना पत्र

महीने चलाया जाएगा।

हरियाणा सरकार की 1.80 लाख वार्षिक आय वाले परिवारों को दी जाने वाली सरकारी योजनाओं के लाभ की तर्ज पर ऐसे परिवारों के बच्चों को भी अग्निवीर कोचिंग की सुविधा निशुल्क होगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार किया जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व बहु–तकनीकी संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए भी कोचिंग सुविधा उपलब्ध होगी।

बैठक में मुख्यमंत्री ने एयर मार्शल मानवेन्द्र सिंह को जानकारी दी कि हाल ही में केन्द्र सरकार ने पूरे देश में 10 नये सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की है। हरियाणा में कुंजपुरा व रेवाड़ी में 2 सैनिक स्कूल पहले से ही संचालित हैं। हमारा प्रयास है कि 10 नये सैनिक स्कूलों में से 1 सैनिक स्कूल हरियाणा को मिले। हमारे पास इस स्कूल के लिए झज्जर जिले के मातनहेल में पहले से ही जमीन उपलब्ध है।

हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक

(दिनांक 29.07.22)

विषय: हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक।

प्रभाव: माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसमें

- मंत्रिमंडल की बैठक में सशस्त्र बलों (सेना,नौसेना और वायु सेना) के परिवारों/दिव्यांग सैनिकों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान के संबंध में संशोधित नीति/निर्देशों को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री की 21 अक्टूबर, 2021 की घोषणा के अनुसार, हरियाणा ने सशस्त्र बल (सेना,

साप्ताहिक सूचना पत्र

नौसेना और वायुसेना) जो युद्ध/ऑप्रेशनल क्षेत्र में, आतंकवादी गतिविधियों और प्राकृतिक आपदाओं आदि में मारेगए/दिव्यांग कर्मियों के लिए निशक्तता के आधार पर अनुग्रह अनुदान की दरों में वृद्धि की है। संशोधित दरों के अनुसार, दिव्यांग सशस्त्र बलों (सेना, नौसेना और वायु सेना) को 75 प्रतिशत या अधिक निशक्तता के मामले में 35 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जा रही है। इससे पूर्व यह राशि 15 लाख रुपये थी। इसीप्रकार, 50 प्रतिशत से 74 प्रतिशत तक निशक्तता के मामले में 25 लाख रुपये तथा 25 प्रतिशतसे 49 प्रतिशत तक निशक्तता के मामले में 15 लाख रुपये अनुग्रह राशि प्रदान की जा रही है। पहले यह राशि क्रमशः 10 लाख और 5 लाख रुपये थी।

- दीनदयाल जन आवास योजना में संशोधन को मंजूरी

मंत्रिमंडल की बैठक में दीन दयाल जन आवास योजना–अफोर्डेबल प्लॉटेड हाउसिंग पॉलिसी, 2016 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने और किफायती आवास परियोजनाओं का लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार ने दीन दयाल जन आवास योजना–अफोर्डेबल प्लॉटेड हाउसिंग पॉलिसी, 2016 में 50 प्रतिशत बिक्री योग्य क्षेत्र को फ्रीज करने के प्रावधान को हटा दिया है।

- हरियाणा सरकार ने मोटर वाहन कर की बकाया राशि पर लगने वाली पैनल्टी में किया संशोधन

हरियाणा में वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में विभिन्न

साप्ताहिक सूचना पत्र

श्रेणियों के मोटर वाहनों पर लगाए जाने वाले मोटर वाहन कर की जुर्माना (पैनल्टी) दरों को युक्तिसंगत और संशोधित करने का निर्णय लिया संशोधन के अनुसार, वाहन मालिक या वह व्यक्ति, जिसके कब्जे या नियंत्रण में वाहन है, उनके द्वारा निर्धारित समय में मोटर वाहन के संबंध में देय कर भुगतान नहीं किया गया है, तो देयकर के भुगतान के अलावा वे देय कर पर 3 प्रतिशत प्रति माह की दर से पैनल्टी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। वर्तमान में मोटर वाहन कर की बकाया राशि पर प्रत्येक दिन की देरी के लिए 0.5 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से पैनल्टी, जोकि 15 प्रतिशत प्रति माह बनता है, तथा पैनल्टी पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज लगाया जाता है। कर प्रशासन को तर्कसंगत, सरल और कुशल बनाने के लिए यह पाया गया कि जुर्माने की दर अधिक है और बेहतर कर अनुपालन सुनिष्चित करने के लिए इसे युक्ति संगत बनाने की आवष्यकता है।

- हरियाणा लैंडपूलिंग पॉलिसी' 2022 को दी मंजूरी

मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लैंड पूलिंग पॉलिसी – 2022 को मंजूरी प्रदान की गई। यह नीति मुख्यरूप से शहरी करण और औद्योगीकरण के उद्देष्यों के लिए लैंडबैंक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। चूंकि भूमि मालिक विकास प्रक्रिया में भागीदार होंगे, इसलिए नीति का उद्देष्य भूमि के आवंटन को रिक्त भूमि (रॉ लैंड) की लागत से जोड़कर उन्हें अधिकतम लाभ प्रदान करना है। नीतिमें विभिन्न चरणों में समय–सीमा निर्धारित की गई है ताकि भूमि मालिकों के हितों की सुरक्षित की जा सके और समय बद्ध तरीके से भूमि विकास के उद्देष्य को प्राप्त किया जा सके।

यह नीति विकास योजना में निर्दिष्ट भूमि उपयोग के अनुरूप भूमि के लिए लागू होगी। साथ ही, यह नीति हरियाणा में किसी अन्य क्षेत्र के संबंध में भी लागू होगी, जहां विकास का उद्देष्य बुनियादी ढांचा या औद्योगिक विकास हो। डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन द्वारा भू–स्वामियों को एक भूमि अधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जोट्रेड या मोर्टगेज रखा जा सकता है।

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियंत्रण) आदेश, 2022 को मंजूरी

मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा

नियंत्रण) आदेश, 2022 की स्वीकृति के संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत उचित मूल्य की दुकान जारी करने के लिए 33: महिला आरक्षण दिया जाएगा। उचित मूल्यकी दुकान का लाइसेंस कम से कम 300 लाभार्थियों के राशन कार्ड के लिए दिया जाएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इस उद्देष्य के लिए एक गांव को एक ईकाई के रूप में माना जाएगा। गांव के 300 से कम राशन कार्ड के लिए भी उचित मूल्य की दुकान का लाइसेंस जारी किया जाएगा। राशन दुकान की सेवाओं को ऑनलाइन या अन्य तंत्र के माध्यम से वितरित किया जाएगा।

हरियाणा इंटरप्राइजेज प्रोमोषन बोर्ड (एचईपीबी) की 14वी बैठक

(दिनांक 29.07.22)

विषय: हरियाणा इंटरप्राइजेज प्रोमोशन बोर्ड (एचईपीबी)की 14वी बैठक।

प्रभाव: माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित हरियाणा इंटरप्राइजेज प्रोमोशन बोर्ड (एचईपीबी) की 14वी बैठक में एम/एस सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसएमआईपीएल) के लिए 67.62 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि के विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह परियोजना हरियाणा में ऑटोमोबाइल विनिर्माण के मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करेगी और हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। वर्तमान में कंपनी खेरखी धौला, गुरुग्राम में 1 हजार करोड़ रुपये के निवेश के साथ भारत और विदेशों में ग्राहकों की जरूरतों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र की सालाना उत्पादन क्षमता 11 लाख दोपहिया वाहनों की है। इस ने राज्य के भीतर लगभग 3500 नौकरियों का सृजन किया है। अब ये नई सुविधा गुड़गांव, हरियाणा में इस कंपनी की मौजूदा क्षमता में इजाफा करेगी।

साप्ताहिक सूचना पत्र

मादक पदार्थों की तस्करी व राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन

(दिनांक 30.07.22)

विषय: मादक पदार्थों की तस्करी व राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन।

प्रभाव: उत्तरी राज्यों से नशे की बुराई को जड़मूल से उखाड़ने के लिए और इस दिशा में ठोस रणनीतियां बनाने के उद्देष्य से केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नशाखोरी और मादक पदार्थों की तस्करी आज दुनियाभर के लोगों के लिए चिंता का विषय है। यह समस्या किसी एक राष्ट्र की नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया ही इसकी चपेट में है। विभिन्न कारणों से हमारा युवा वर्ग ही नहीं, बल्कि बच्चे भी नशे की चपेट में आ रहे हैं। नशाखोरी की समस्या से देश के लगभग सभी राज्य जूझ रहे हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमे नशे के विरुद्ध एक सामूहिक लड़ाई लड़नी होगी। यदि किसी एक राज्य में नशाखोरी व मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के विरुद्ध पुलिस द्वारा सख्ती की जाती है, तो नशे के सौदागर पड़ोसी राज्यों की ओर रूख करने लगते हैं। नशा

बेचने वालों का नेटवर्क पूरे देश में फैला है। विभिन्न राज्यों की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां तो इनसे लड़ ही रही हैं। लेकिन विभिन्न राज्यों की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आपसी तालमेल से एकजुट होकर काम करें तो इस समस्या पर अंकुश लगाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी व राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर आयोजित पूर्व के सम्मेलनों में हुए निर्णयों के अनुसार हमने न केवल कारगर कदम उठाए हैं, बल्कि उनके परिणाम भी आने लगे हैं। हरियाणा में हर महीने NDPS एक्ट के 200 से अधिक मुकदमे दर्ज होते हैं। राज्य में 30 जून तक 1913 मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें 2661 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जून 2022 तक 253 ड्रग्स तस्करों की करीब 32 करोड़ रुपए की काली कमाई जब्त की है तथा 13 करोड़ रुपए मूल्य की सम्पति को जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि NDPS एक्ट के तहत ही प्रदेश में 142 नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं। इनके अलावा सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य एवं नशा मुक्ति वार्ड खोले गए हैं। प्रदेश के हर जिले के सिविल अस्पताल में भी नशा मुक्ति केंद्र खोले जा रहे हैं। अब तक 13 जिलों में ये केंद्र खोले जा चुके हैं। जहां नशामुक्ति केंद्र स्थापित नहीं हैं उन सभी जिलों के सिविल अस्पतालों में मनोचिकित्सक नशामुक्ति सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अब तक हिसार व रोहतक जेल में ये केंद्र खोले जा चुके हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम नशे के आदी व्यक्तियों की पहचान, उपचार और आर्थिक रूप से उनका पुनर्वास कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए 'हरियाणा राज्य मादक पदार्थ रोकथाम समिति का गठन कर रहे हैं। यह समिति भी नशे के कारण होने वाली सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य व अन्य हानियों के बारे में अनुसंधान कर लोगों को जागरूक करने का काम करेगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इस लड़ाई में आई.टी. का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। 'प्रयास' नाम के मोबाइल एप के जरिए हम नशे के आदी लोगों के बारे में आँकड़े जुटा रहे हैं और उनकी नशामुक्ति के लिए कारगर कदम उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि ऐसी प्रतिबंधित दवाओं, जिनका इस्तेमाल नशे के रूप में किया

साप्ताहिक सूचना पत्र

जाना सम्भव है, उन्हें ट्रैक करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उन पर युनीक सीरियल नम्बर डलवाया जाना अनिवार्य किया जाना चाहिए। अपराधों, अपराधियों, पीड़ितों आदि से संबंधित सभी गतिविधियों का केंद्रीकृत राज्य डेटाबेस बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर HAWK विकसित किया है। इससे नशे के कारोबारियों पर नकेल कसने में मदद मिली है।

बच्चों और युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए एक कार्यक्रम 'धाकड़' स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के स्तर पर शुरू किया है। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो द्वारा तैयार किए गए स्टेट एक्शन प्लान के तहत प्रस्तावित धाकड़ प्रोग्राम के माध्यम से हरियाणा राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों के छात्रों को नशे के कुप्रभावों से अवगत करवाना व उसके विरूद्ध जागरूक करना है। स्टेट एक्शन प्लान के तहत ग्राम व वार्ड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक मिशन टीमों का गठन किया जाएगा। इनमें सरपंच, ग्राम सचिव, पटवारी, सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी, स्कूल के प्राचार्य, बीट प्रभारी, नंबरदार, महिला सदस्य आदि को शामिल किया जाएगा। इस प्रकार आम जनता की भागीदारी से इसे जन आंदोलन के रूप में लागू किया जाएगा।

साप्ताहिक सूचना पत्र

सुश0ाासन सहयोगियों (सीएमजीजीए) के छठे बैच का लघु दीक्षांत समारोह

(दिनांक 31.07.22)

विषय: सुशासन सहयोगियों (सीएमजीजीए) के छठे बैच का लघु दीक्षांत समारोह।

प्रभाव: आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सुशासन सहयोगियों के साथ बैठक की। यह CMGGA का छठा बैच था जिसे आज औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री जी ने विदाई भी दी।

इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों के माध्यम से लगभग 50 ऐसी योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए जिनका सीधा लाभ प्रदेश के जरूरतमंद व्यक्तियों को मिला है। इसके अलावा इन फ्लैगशीप योजनाओं एवं कार्यक्रमों की देशभर में सराहना भी हुई है।

मुख्यमंत्री जी ने इस मौके पर सभी

साप्ताहिक सूचना पत्र

सुशासन सहयोगियों से सीधा संवाद कर उनसे अनुभव सांझा किए तथा उन्हें प्रमाण पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री जी ने सीएमजीजीए की वार्षिक पत्रिका ''दुरबीन'', सीएमजीजीए के रिसर्च पर आधारित पुस्तिक ''एन आउट लुक फोर चेंज'' तथा सीएमजीजीए द्वारा चलाई गई जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित ''स्ट्रेंथनिंग वेल्फेयर डिलीवरी इन हरियाणा'' नामक तीन पुस्तकों का विमोचन भी किया ।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सुशासन सहयोगियों द्वारा सरकार से जुड़कर, सरकार की योजनाओं का सही क्रियान्वन में सहयोग करना काबिले तारीफ रहा है। सुशासन सहयोगियों के लगातार कार्य करने से ही पीपीपी, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जैसी कारगर योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू किया जा सका । इन योजनाओं के लिए सुशासन सहयोगियों ने बढ चढ कर धरातल पर कार्य किया और लक्ष्य को प्राप्त करने में भरपूर सहयोग किया। इसके लिए सभी सुशासन सहयोगी बधाई के पात्र हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गत दिनों

साप्ताहिक सूचना पत्र

प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में हरियाणा की परिवार पहचान पत्र योजना को अधिकांश मुख्यमंत्रियों ने अपनाने की बात कही है। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हरियाणा में टीम भेजकर इस योजना के प्रारूप और क्रियान्वयन को भी समझा है। इस प्रकार हरियाणा की बहुत सी योजनाओं की कई राज्य न केवल प्रशंसा कर रहे हैं, बल्कि उनका अनुसरण भी कर रहे हैं । यहां तक कि सीएमजीजीए प्रोजैक्ट को भी कई राज्य अपना रहे हैं यह भी प्रदेश के लिए बड़ा गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इज आफ लिविंग के कंसेप्ट पर प्रदेश के लोगों का जीवन सरल व सुगम बनाने पर कार्य किया जा रहा है। इससे लोगों का संतुष्टि लेवल बढाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक लेवल में कुछ इच्छाएं होती हैं जिनमें टेलेंट, क्षमता और योग्यता का लेवल मिले उसे सही संतुष्टि लेवल कहा जा सकता है। एसोसिएट द्वारा कृषि, गरीबी उन्मूलन, ई–गवर्नेंस, शिक्षा और सेवा वितरण जैसे क्षेत्रों में किए प्रमुख कार्य इस उद्देष्य की पूर्ति के लिए मील का पत्थर साबित हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री जी ने सभी सुशासन सहयोगियों के लिए उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए। उनके आगे आने वाले जीवन के लिए बधाई दी। और हरियाणा के विकास में किए गए उनके योगदान की सराहना भी की।